संख्या- 37/2024/1157/001-78-02099/37/2024

प्रेषक,

राधेश्याम

संयुक्त सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,

कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर,2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति- 2021 हेतु गठित पीएमयू को शुल्क भुगतान के लिए धनराशि रू0 25,00,000 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी: आईसीपी:9064(2024-2025) दिनांक 30-07-2024 एवं पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2024-2025)1 दिनांक 03-07-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 हेतु गठित पीएमयू हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 213.43 लाख के सापेक्ष रु0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की वितीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर तात्कालिक आवश्यकता होने पर वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(7) अपरिहार्यता की स्थिति में ही स्वीकृत धनराशि आहरित कर स्टेट बैक ऑफ इण्डिया / राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

(8) भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व 30प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं पीएमयू में नियोजित जनशक्ति एवं कार्यावाधि के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

(11) पीएमयू में कार्यरत जनशक्ति के मासिक निस्पादन आख्या (MPR) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(13) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) मैनपावर की सेवाएं लिए जाने हेतु उनकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी का होगा।

(16) कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001600 उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार एवं वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभाग द्वारा अंकित अशासकीय संख्या-E-6-74-X-2024-25, दिनांक 02-09-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राधेश्याम
संयुक्त सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या- 37/2024/1157(1)/001-78-02099/37/2024 एवं दिनांक यथोक्त:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0 ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ ।
10. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम,आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राधेश्याम
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।